भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4287

जिसका उत्तर गुरुवार, 20 फरवरी 2014 को दिया जाना है

रुग्ण मिलें

4287. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रुग्ण मिलों की अप्रत्याशित रूप से बढ़ती संख्या की समीक्षा करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति के गठन हेतु कोई कदम उठाया गया है या उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार रूग्ण मिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जहां तक भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का संबंध है, इस तरह की किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख): प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग): भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों, नेपा लिमिटेड और नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड, जहां पेपर मिलें चल रही हैं, के लिए सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

*****